Title: Need to lift ban on production of 'Khesari Dal' - laid.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश में जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो रहा है। पहली हरित क्रांति के बाद एक तरफ खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चला रहे हैं। इस दोहरी मानसिकता के कारण कृषि क्षेत्र का सही मायनों में विकास नहीं हो पा रहा है। आज हम दलहन, तिलहनों तथा अन्य कई कृषि उत्पादों का आयात कर रहे हैं। आज गेहूं का भी आयात हो रहा है आयात के कृषि उत्पादों के लिए भारी दाम चुकाये जाते हैं, लेकिन स्वदेशी कृषकों को न्यूनतम दाम देने में सरकार हिचकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सरकार द्वारा कतिपय राज्यों की विभिन्न मिलों को चयनित कर वहां गेहूं, चावल और दलहनों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने की योजना है। हमारे यहां के चन्द्रपुर और गड़चिरौली जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन हमारे यहां पर जो खेसरी (लाखोडी) दल विपरीत स्थिति में उत्पादन देती है को दलहन उत्पादन में शामिल किया गया होता तो हम दलहनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते थे। लेकिन केन्द्र सरकार इसके उत्पादन की अनुमति नहीं देने और राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण खेसरी दाल का अधिकृत रूप से उत्पादन नहीं लिया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि खेसरी दाल के उत्पादन को स्वीकृति देने के लिए सभी अवरोधों को तत्काल प्रभाव से दूर करे और इसके उत्पादन का रास्ता प्रशस्त करे।